भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2545

दिनांक 04/08/2026 को उत्तरार्थ

स्वामित्व योजना

†2545. श्री एम. मल्लेश बाबू:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक के कोलार जिले के गांवों से संबंधित ग्राम आबादी सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत तकनीक से मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत तैयार किए गए भू-स्थानिक डेटासेट को पीएम गतिशक्ति के साथ एकीकृत करने की संभावना का परीक्षण किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विकास योजना के लिए भू-संपत्ति और भू-स्थानिक डेटा के उपयोग के संबंध में संबंधित मंत्रालयों, राज्य एजेंसियों, स्थानीय निकायों और तकनीकी संस्थानों के साथ आयोजित बैठकों/परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे डेटासेट के एकीकरण से ग्रामीण सड़कों, पेयजल प्रणालियों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, सौर अवसंरचना और सामुदायिक संपत्तियों की योजना में सुधार होने की उम्मीद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य डिजिटल शासन प्रणालियों, भूमि सूचना प्रणालियों और भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के साथ 'स्वामित्व' डेटासेट की अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) जिले में ग्रामीण योजना, योजनाओं के अभिसरण और प्रभावी शासन की सहायता करने के लिए ग्राम-स्तरीय भू-स्थानिक सूचना का लाभ उठाने का भविष्य का रोडमैप क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हाँ। सरकार ने गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा मानचित्रण (स्वामित्व) योजना के तहत तैयार किए गए भू-स्थानिक डेटासेट को एकीकृत करने की संभावनाओं की जांच की है। कर्नाटक सहित 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए भू-स्थानिक डेटासेट को 'पीएम गति शक्ति' के साथ एकीकृत करने के लिए साझा किया गया है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय ने अब तक मंत्रालयों/विभागों, राज्य एजेंसियों, ग्रामीण स्थानीय निकायों और तकनीकी संस्थाओं को आमंत्रित करते हुए राष्ट्रीय स्तर की 7 कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इन परामर्शों का उद्देश्य स्वामित्व डेटा के उपयोग और ग्राम मानचित्र ऐप के साथ इसके एकीकरण की बेहतर समझ को बढ़ावा देना था। ग्राम मानचित्र ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक स्थानिक योजना ऐप है, जो ग्राम पंचायतों के लिए बेहतर विकास योजना बनाने में मदद करता है। कार्यशाला का विवरण अनुलग्नक-I में संलग्न दिया गया है।

(ग) जी हाँ। इस मंत्रालय द्वारा विकसित 'ग्राम मानचित्र' ऐप एक स्थानिक नियोजन ऐप है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके योजना बनाने के लिए ग्राम पंचायत उपयोगकर्ताओं को सहायता करता है और सुविधा प्रदान करता है। इस ऐप में सड़क का अनुमान तैयार करने, स्ट्रीट लाइट का अनुमान बनाने, सौर क्षमता का आकलन करने जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। स्वामित्व योजना के तहत तैयार की गई उच्च-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन इमेज को ग्राम मानचित्र ऐप के साथ जोड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल पंचायत स्तर पर प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने के लिए किया जाता है, ताकि गांवों की सड़कों, पीने के पानी की व्यवस्था, जल निकासी नेटवर्क की योजनाओं, सार्वजनिक सुविधाओं, सौर अवसंरचना और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नियोजन को बेहतर बनाया जा सके।

(घ) जी हां। मंत्रालय ने स्वामित्व डेटासेट को अन्य डिजिटल शासन फ्रेमवर्क, भूमि सूचना प्रणालियों और भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के साथ अंतर-संचालनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। उदाहरण के लिए, मंत्रालय ने स्वामित्व डेटासेट को ग्राम मानचित्र जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया है। इन डेटासेट को पीएम गति

शक्ति जैसे अन्य भू-स्थानिक प्लेटफार्मों के साथ भी साझा किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी अपने प्लेटफार्मों के साथ स्वामित्व डेटासेट की अंतर-संचालनीयता को मजबूत बनाते हैं जैसे कर्नाटक के ई-स्वाथु प्रणाली के साथ स्वामित्व डेटासेट की अंतर-संचालनीयता।

(ङ) स्वामित्व योजना के तहत, कर्नाटक राज्य द्वारा 15 जिलों (कोलार जिले सहित) में ड्रोन उड़ान का आयोजन किया जा रहा है, जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा कर्नाटक के शेष 16 जिलों में ड्रोन उड़ान का आयोजन किया जा रहा है। कोलार जिले में कुल 1,817 गांवों में ड्रोन उड़ान का कार्य पूरा हो चुका है, 711 मानचित्र-1 साझा किए गए हैं, 286 गांवों में जमीनी स्तर पर सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है और 230 गांवों के लिए 20,364 संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

इस मंत्रालय की भविष्य की योजना में कोलर जिले सहित जिलों की ग्राम पंचायतों द्वारा साक्ष्य-आधारित ग्रामीण योजना जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय, पीएम गतिशक्ति के तहत अवसंरचना और परिसंपत्ति योजना, बेहतर सेवा प्रदायगी और सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए स्वामित्व योजना और ग्राम मानचित्र ऐप के भू-स्थानिक डेटा का लाभ उठाने की परिकल्पना की गई है।

******

अनुलग्नक-I

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकास योजना के लिए कैडस्ट्रल और भू-स्थानिक डेटा के उपयोग के संबंध में मंत्रालयों, राज्य एजेंसियों, स्थानीय निकायों और तकनीकी संस्थाओं की भागीदारी के साथ 7 कार्यशालाओं में किए गए परामर्श का विवरण:

क्रम सं	कार्यशाला	तिथि	स्थान
1.	एमओपीआर की 'आइकॉनिक वीक' बैठक के दौरान स्वामित्व डेटा की मदद से स्थानिक और विकास योजना पर चर्चा	अप्रैल 2022	नई दिल्ली
2.	एमओपीआर की स्वामित्व योजना कार्यशाला के दौरान स्थानिक और विकास योजना पर चर्चा	नवंबर 2022	भोपाल
3.	एमओपीआर द्वारा ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला	फ़रवरी 2024	भोपाल
4.	स्वामित्व और भूमि प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान स्वामित्व डेटा का उपयोग करके योजना बनाने के लिए 'ग्राम मानचित्र' के उपयोग पर चर्चा	मार्च 2025	गुरूग्राम
5.	एमओपीआर द्वारा बेहतर ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला	जुलाई 2025	भोपाल
6.	एमओपीआर द्वारा जियो-स्थानिक विश्व सम्मेलन के दौरान स्थानिक और विकास योजना पर चर्चा	दिसंबर 2025	नई दिल्ली
7.	एमओपीआर द्वारा स्वामित्व डेटा का उपयोग करके जल निकासी नेटवर्क की योजना पर चर्चा	जनवरी 2026	वाराणसी

***